



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ।
17 दिसंबर को लोकसभा में केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश करने के साथ ही देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने की दिशा में एक कदम और बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मंशा व्यक्त करती रही है ताकि इस पर सांसदीय समिति के माध्यम से गंभीर मंथन और चिंतन हो सके। हालांकि अभी एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ते कदमों में स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया बाकी है जिस

सम्पादकीय

अडानी मुद्दे पर कुछ दिखावे के लिए राहुल व कांग्रेस के साथ जुड़े

यह संयोग है या प्रयोग कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के कन्नी काटी और अडानी मुद्दे पर संसद ठप्प करने में शामिल होने से इनकार किया। उसके बाद ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की चर्चा शुरू हो गई? यह सही है कि ममता बनर्जी ने खुद ही चर्चा शुरू कराई। उन्होंने कहा कि, इंडिया ब्लॉक का गठन उन्होंने किया है और इसलिए मौका मिले तो उसका नेतृत्व करना चाहेंगी। हालांकि हकीकत यह है कि विपक्ष का गठबंधन बनाने का ममता का, के चंद्रशेखर राव का और अरविंद केजरीवाल का प्रयास विफल था। अभी जो विपक्षी गठबंधन है वह नीतीश कुमार का बनाया है, जिसमें ममता बनर्जी भी थीं और बाद में नीतीश व ममता दोनों बाहर हो गए। परंतु पहले ममता की पार्टी तुणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह अडानी के मसले पर संसद ठप्प करने के पक्ष में नहीं है और उसके सांसदों ने कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन में शामिल होना बंद किया। उसके बाद ममता ने इंडिया ब्लॉक का नेता बनने की इच्छा जाहिर की और फिर एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन करने लगीं।

उद्धव ठाकरे की शिव सेना के नेता संजय राउत ने भी उनका समर्थन किया तो शरद पवार ने भी उनका साथ दिया। कांग्रेस के ऑल वेदर फ्रेंड माने जाने वाले लालू यादव ने तो यहां तक कहा कि ममता बनर्जी को नेता बना देना चाहिए और कांग्रेस अगर विरोध करती है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनमें से उद्धव ठाकरे एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने खुल कर अडानी का विरोध किया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका विरोध महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक सीमित था और वह भी अडानी के एक धारावी प्रोजेक्ट को लेकर था। सिद्धांत रूप से वे अडानी, अंबानी विरोधी नहीं माने जाते हैं। आखिर अंबानी के यहां शादी में बाराती बन कर चितने नेता शामिल हुए थे उनमें राहुल या नेहरू गांधी परिवार के अलावा बाकी सारे विपक्षी नेता शामिल ही थे। ममता भी थीं और लालू प्रसाद का पूरा परिवार भी था और अखिलेश यादव भी सपरिवार पहुंचे थे। लेफ्ट के नेता जरूर नहीं गए थे लेकिन संभवतः उनको बुलाया भी नहीं गया हो। लेकिन सोनिया गांधी के परिवार को न्योता देने तो मुकेश अंबानी खुद पहुंचे थे।

सो, पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी के नाम पर संसद ठप्प करने इनकार किया और उसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी यही लाइन पकड़ी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सांसद पत्नी खिंपल यादव ने कहा कि अडानी मामले से सपा का कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस का भी क्या लेना देना है? फिर भी कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है क्योंकि एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह, पत्रकारों का संगठन और विदेशी सरकारें या उनकी एजेंसियां अडानी समूह को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। अडानी दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रतीक बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों को उछालने से बड़ा राजनीतिक नैस्टिव बनता है। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी यह मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टीयां या तो इससे अलग हो रही हैं या दिखावे के लिए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से अलग हो गई लेकिन लालू प्रसाद और शरद पवार की पार्टी विरोध प्रदर्शन में शामिल है। एक और सत्य कि शरद पवार का तो अडानी विरोध कभी रहा ही नहीं है। फिर उनकी पार्टी के अडानी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह सिर्फ दिखावा है। आखिर चाचा मतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार ने स्वीकार किया है कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन में गतिरोध पैदा हुआ था तो ये सभी लोग अडानी के साथ बैठे थे सरकार बनाने के लिए।



की सबसे बड़ी अदालत अर्थात् सुप्रीम कोर्ट कई बार नेक सलाह दे चुकी है लेकिन वोट की राजनीति के चलते सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के परिजनों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जिसके परिवार में आईएएस, पीसीएस जैसे पदों पर विद्यमान हैं। कोर्ट का आशय था कि आरक्षण की

हालांकि मोदी सरकार आने के बाद से ही 2014 से एक देश एक चुनाव पर चर्चा का सिलसिला चल निकला था। 2017 में नीति आयोग ने इसे उपयुक्तताया और 2018 में संसद के संयुक्तसत्र को संबोधि त करके हुए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इसे सही दिशा बताया।

होने से करीब एक साल तक चुनी हुई सरकार पंगु ही बन कर रह जाती है। इसको राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के चुनावों से इस तरह से समझा जा सकता है। हालांकि यह उदाहरण मात्र है और सभी प्रदेशों पर समान तरीके से लागू होता है। नवंबर दिसंबर में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होते हैं। सरकार बनते ही अपनी प्राथमिकता भी तय कर पाती है जब तक बजट की तैयारी में जुटना पड़ता है क्योंकि अब फरवरी में ही बजट सेशन होने लगे हैं। मई जून में लोकसभा के चुनाव के कारण अप्रैल से ही नहीं अनेक समस्याओं का कारण बन रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग

बांग्लादेश मामले में कूटनीति व राजनीति पर एक कदम आगे निकली ममता बनर्जी

जगदीश यादव । भारत हमेशा से विश्व में शांति का प्रतीक रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में टकराव का माहौल बन गया है। इसे निपटाने के लिए अंतरिम युजुस सरकार नाकाम नजर आती आई है। ऐसे में शांति सेना भेजकर वहां पर शांति स्थापित की जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर तुष्टीकरण से लेकर बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और मीडिया में उक्त खबरें हर रोज आ रही है। ऐसे में भले ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी का उक्त मुद्दे पर कोई रुकन नहीं आया है लेकिन ममता बनर्जी ने सशक्त तौर पर इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को उठाया है और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को नाकाम तक करार दिया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से उपजे एक बयान का जवाब देते हुए साफ कहा कि, अगर वह लोग बिहार, बंगाल ओडिशा जैसे हमारे देश के राज्यों पर कब्जे की बात करेंगे तो वह बैटकर लॉलीपॉप नहीं चूसेंगी। साथ ही

को समर्पित हो जाता है। इसके कुछ समय बाद ही या यों कहे कि परिवर्तित बजट से निपटते निपटते सरकार के सामने स्थानीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का समय हो जाता है और उसके कारण लंबा समय इन चुनावों के कारण आचार संहिता के भेंट चढ़ जाता है। इस बीच में कोई कोई ना कोई उप चुनाव आ जाते हैं तो उसका असर भी चुनी हुई सरकार को भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे चौथा साल पूरा होने को होता है कि सरकार ताबड़तोड़ निर्णय करने लगती है और इनके क्रियान्वयन का समय आते आते चुनाव आचार संहिता लग जाती है। इस तरह से एक बात तो साफ हो जाती है कि पांच साल के लिए चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का कमोबस करीब एक साल का समय तो चुनाव आचार संहिताओं के ही भेंट चढ़ जाता है। यह तो केवल लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के कार्यों के प्रभावित होने का एक उदाहरण मात्र है। अब अलग अलग चुनाव होने से चुनाव पर होने वाले सरकारी और गैर सरकारी खर्च पर भी ध्यान दिया जा सकता है। 1952 के पहले चुनाव में सरकारी व गैरसरकारी जिसमें राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वालों का खर्च भी शामिल है यह करीब 10 करोड़ के आमपास रहा। 2010 के आमचुनाव में 10 हजार करोड़ रु. का व्यय माना जा रहा है जो 2019 में 55 हजार करोड़ और 2024 के आमचुनाव में एक लाख करोड़ को घू गया

है। इसमें चुनाव आयोग, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा होने वाला खर्च शामिल है। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद से ही 2014 से एक देश एक चुनाव पर चर्चा सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आवश्यकताओं को लेकर भी शंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग में संसाधनों का आकलन कर अपनी आवश्यकताएं सरकार को बता दी है उससे लगता है कि चुनाव आयोग भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है। 2029 के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा 7951 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया गया है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों सहित अन्य खर्च अलग होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के सकारात्मक पक्ष भी है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से दुनिया के अन्य देशों जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, फिलिपिंस आदि में भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं। कोविंद कमेटी ने जर्मनी के चुनाव पेटर्न को बेहतर व अनुकरणीय भी माना है। खैर यह अलग बात है। एक साथ साफ हो जाना चाहिए कि एक साथ चुनाव होने से संसाधन तो एक बार जुटाने होंगे पर उसके बाद व्यवस्था सुनिश्चित हो और श्रम संकट ही माना जाएगा। इससे छोटे व स्थानीय दलों के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग पेटर्न प्रभावित

होगा। चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव के लिए मशीनरी भी अधिक लगाने की बात की जाती है तो खर्च व आभारभूत सुविधाओं यथा ईवीएम मशीन, वीवीपेट मशीन, उनके रखरखाव सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आवश्यकताओं को लेकर भी शंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग में संसाधनों का आकलन कर अपनी आवश्यकताएं सरकार को बता दी है उससे लगता है कि चुनाव आयोग भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है। 2029 के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा 7951 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया गया है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों सहित अन्य खर्च अलग होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के सकारात्मक पक्ष भी है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से दुनिया के अन्य देशों जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, फिलिपिंस आदि में भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं। कोविंद कमेटी ने जर्मनी के चुनाव पेटर्न को बेहतर व अनुकरणीय भी माना है। खैर यह अलग बात है। एक साथ साफ हो जाना चाहिए कि एक साथ चुनाव होने से संसाधन तो एक बार जुटाने होंगे पर उसके बाद व्यवस्था सुनिश्चित हो और श्रम संकट ही माना जाएगा। इससे छोटे व स्थानीय दलों के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग पेटर्न प्रभावित

उदासीनता देखी जा रही है वह निश्चित रूप से कम होगी। राजनीतिक दल भले ही आज विरोध कर रहे हैं पर एक साथ चुनाव से उन्हें भी कम मशक्कत व एक बार ही मशक्कत करनी होगी। प्रचार सामग्री से लेकर प्रचार अभियान को आसानी से संचालित किया जा सकेगा। योजनाबद्ध प्रयासों से विधानसभा व लोकसभा प्रत्याशियों का एक साथ प्रचार अभियान संचालित हो सकेगा जिससे अलग अलग चुनाव होने से बार बार होने वाले व्यय में कुछ हद तक राजनीतिक दलों को भी कम खर्च करना पड़ेगा। चुनी हुई सरकारों को बार बार आचार संहिता के संकट से गुजरना नहीं पड़ेगा और सरकार को काम करने का अधिक समय मिल सकेगा। दोनों चुनाव एक साथ होने से भले ही पोलिंग बूथ अधिक बनाने पड़े, मशीनरी अधिक लगानी पड़े पर मतदाताओं और चुनाव कराने वाली मशीनरी के लिए भी सुविधाजनक होगा। एक बात यह भी कि असांजिक तत्वों की गतिविधियां भी काफी हद तक कम हो सकेगी। इससे सरकारी संसाधनों की बचत, मानव संसाधन को बार बार नियोजित करने से होने वाले सरकारी कार्य में बाधा में बचत और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बार बार चुनाव के स्थान पर एक साथ चुनाव होने से खर्चों में भी कमी आएगी। देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में बढ़ता कदम माना जा सकता है।



बाजपा के नेता भी लगभग मौन ही है। लेकिन बंगाल में नेता प्रतिक्रिया व भाजपा नेता शुभेंद्रु अहिकारी जोरदार तौर पर उक्त मामले पर विरोध व्यक्त कर रहें हैं और बांग्लादेश को चेता भी रहे हैं। हालांकि अब जाकर बांग्लादेश ने यह माना कि शेख हसीना सरकार के अपदरथ होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि, इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पांच अगस्त से 22 अक्टूबर के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं को लेकर कुल 88 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मामलें और गिरफ्तारियां और बढ़ सकती

है, क्योंकि कई क्षेत्रों में हिंसा की नई घटनाएं सामने आई हैं। देखा जाए तो दरअसल, बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्य हिन्दू उत्पीड़न कोई नई बात नहीं हैं। वहां कोई भी सरकार हो निशाने पर हिन्दू महेशा रहे हैं।

बात बांग्लादेश में तत्कालीन घटना की करें तो इस्कोन के संस्थापी चिन्मय कृष्ण दास के गिरफ्तारी से शुरु हुई। पहले इन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में फिर इनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जेल में इन साधुओं को बाहर से भोजन उपलब्ध । कराने के नाते भी गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि अपने भोजन संबंधित नियमों के नाते ये कुछ भी और कही का भी खाना नहीं खा सकते हैं। फिर जब

हिन्दू समाज ने विरोध शुरु किया तो उनके उपर हमलें शुरु हो गए और हिंदू समुदाय को आज वहां यातना झेलनी पड रही है। बहरहाल दो देशों को सामने रख कर अगर सरल शब्दों में राजनीति व कूटनीति की बात करे तो कहा जा सकता है कि राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई कह नहीं सकता। यहाँ कुछ भी दावे के साथ स्थायी नहीं होता है। लेकिन कूटनीति की बात करे तो कहा जा सकता है कि जब बात देश व उससे जुड़े लोग और मुद्दों की बात हो तो वहाँ राजनीति नहीं की जा सकती बरन वहाँ कूटनीति ज्यादातर कारगर होती है। देखा जाए तो उपरोक्त मुद्दे पर ममता बनर्जी एक कदम आगे निकली दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट की नेक सलाह

समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर भी अमल होगा, यह आसार नहीं दिखते क्योंकि चुनाव के समय सरकार का लाभ नही मिलना और बेरोजगारी भलता से वोट मिल रहे हैं तो मुफ्त राशन को कैसे बंद किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि गरीब लोगों को केवल मुफ्त राशन देने पर ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार दिए जाने पर भी सरकार को काम करना चाहिए। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन की व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने 9 दिसंबर को खाद्य सुस्सा अधिनियम के तहत भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि लोगों को कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं? दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की बेंच के

सामने एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत त सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। दलील में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुस्सा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं? हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर और क्षमता निर्माण पर क्यों नहीं काम करते? प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि वे केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। मगर नवीनतम आदेश में कहा गया है कि यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है और अगर वह इंसान ई-श्रम पोर्टल

पर रजिस्टर्ड है, तो उसे भी केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबसे सत्ता में आए हैं, अभियान और योजनाओं की लंबी फेहरिस्त तैयार कर दी है। मेक इन इंडिया हो या वोकल फॉर लोकल अथवा एक जिला एक उत्पाद, इन सभी योजनाओं ने देश के छोटे कारोबारी से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका उपलब्ध कराया है। मोदी सरकार की सफल योजनाओं की बात करें तो इसकी सूची काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम यहां 3 सबसे सफल स्कीम की चर्चा करेंगे। इसमें से दो योजनाएं तो ऐसी हैं कि जिसका फायदा देश की करीब आधी जनसंख्या को मिल रहा है। पीएम मोदी ने साल 2014 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले जिस योजना का ऐलान किया था, उसे आज पूरी दुनिया में

सराहा जा रहा है। यह योजना न सिर्फ गरीब परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक हथियार साबित हुई, बल्कि देश की महिलाओं को भी मजबूत बनाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं जनधन योजना की। 28 अगस्त, 2014 को लागू हुई जनधन योजना का फायदा अब तक करीब 53 करोड़ लोगों को मिल चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में सफलता की पूरी कहानी बयां करता है। योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला, क्योंकि अभी तक उनके पास आर्थिक आजादी के लिए कोई विकल्प या टूल नहीं था। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा खाते महिलाओं के ही खोले गए। देश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पास अपना बैंक भालता होने से आर्थिक आजादी की राह खुल गई। आज सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। इससे बिचौलियों का धंधा तो बंद हुआ ही, गरीबों के हाथ में आ रहे पैसे की

सुस्सा भी सुनिश्चित हो गई। इस खाते में लोगों को 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। जाहिर है कि अब उन्हें इमरजेंसी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि इस योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी कर चुके हैं। सबसे सफल योजनाओं की बात की जाए तो मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना ने देश के 80 करोड़ लोगों को संभाल रखा है। यह भारत की आधी जनसंख्या से भी बड़ा आंकड़ा है। इस योजना की शुरुआत उस समय हुई थी, जब भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। देश में लगे 76 दिन लंबे लॉकडाउन में लोगों का कामकाज ठप पड़ गया था। तब पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को घर बैठे मुफ्त राशन बांटने का मिर्मा उठाया और करीब 4 साल से यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है।

दीया मिर्जा की पहली फिल्म द्वारा रिलीज

दीया मिर्जा बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइनों में से एक हैं। हाल ही में उनकी पहली फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' दोबारा रिलीज हुई, जिस पर ऑडियंस ने खूब प्यार लुटाया। इस बीच दीया मिर्जा ने कहा कि अगर उनकी सलमान खान के साथ फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' फिर से थिएटर में दस्तक देती है, तो उसे भी दर्शकों से बहुत प्यार मिल सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान दीया ने सलमान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह सलमान खान सेट पर उनकी केयर करते थे क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में नई थीं। एक इंटरव्यू में दीया मिर्जा ने 'तुमको ना भूल पाएंगे' फिल्म की शूटिंग को लेकर बात की। दीया मिर्जा ने राजस्थान में सलमान खान के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां सैकड़ों लोग उन्हें घेर लेते थे, लेकिन सलमान ने सुनिश्चित किया कि दीया सेफ रहें। दीया मिर्जा ने बताया, 'आजकल सेट पर जो जेंडर बैलेंस दिखता है, वो उन दिनों में नहीं था। जब तक सेट पर महिला डांसर नहीं होती थीं, वहां मुश्किल से ही महिलाएं होती थीं। यह एक पुरुष-प्रधान जगह थी। मुझे याद है कि सलमान बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही केयर करने वाले थे।' उन्होंने बताया, 'हम राजस्थान में बिदिया चमके चूड़ी खनके गाने की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन जब हम वापस आ रहे थे, सैकड़ों लोग हमारा पीछा कर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे और यह काफी ज्यादा था। सलमान और मुझे सिक्योरिटी के साथ एक कार में भेजा गया ताकि हम सुरक्षित रहें क्योंकि जहां हम शूटिंग कर रहे थे, वह जगह बहुत भीड़भाड़ वाली थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे पहले कार में बिठाया जाए।' **MgQhZ**

राशि खन्ना आईएमडीबी की लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी की साप्ताहिक लिस्ट में बनाई अपनी जगह

राशि खन्ना ने इस सप्ताह आईएमडीबी की ट्रेडिंग सूची में स्थान हासिल करके एक बार फिर अपना पैर इंडिया स्टारडम साबित किया है। यह प्रतिष्ठित फीचर वैश्विक स्तर पर धूम मचाने वाले भारतीय सितारों को उजागर करता है, जो अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों और अन्य को उनके प्रभाव और अपील के लिए मान्यता देती हैं। राशि का सूची में शामिल होना उनकी बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों से मिली प्रशंसा को दर्शाता है। उन्होंने हाल ही में द साबरमती रिपोर्ट में निडर पत्रकार अमृता गिल की भूमिका निभाते हुए एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया। राशि के दिलचस्प चित्रण को दर्शकों और आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिससे एक बहुमुखी कलाकार के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। विक्रान्त मैसी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए, जिन्होंने एक पत्रकार की भूमिका भी निभाई, उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्म की मनोरंजक कहानी में गहराई जोड़ दी। गोधरा के पास साबरमती एक्सप्रेस घटना के आसपास की दुखद घटनाओं पर आधारित, यह फिल्म इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर प्रकाश डालती है, जिसमें राशि का प्रदर्शन एक आकर्षण के रूप में सामने आता है। इसके अलावा राशि अपनी आगामी फिल्म तलाशों में एक में विक्रान्त मैसी के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो एक और आकर्षक सहयोग होने का वादा करती है। इसके अतिरिक्त, वह अपनी तेलुगु फिल्म तेलुगु कड़ा की रिलीज के लिए तैयारी कर रही हैं। आईएमडीबी की ट्रेडिंग सूची में राशि की उपस्थिति न केवल उनकी अपार प्रतिभा को रेखांकित करती है, बल्कि उन्हें भारतीय मनोरंजन परिवृष्ट में सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक के रूप में भी चिह्नित करती है।



जेलर 2 के प्रमो शूट से पहले रजनीकांत का शिल्पा व राजकुंद्रा के कई डिवाइस सीज धमाका, ब्रेकिंग बैड से इंपायर्ड पोस्टर किए रिलीज



हैदराबादरू रजनीकांत की जेलर 2 मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और हो भी क्यों ना जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. सीक्वल के लिए अनुमानित प्रमो शूट से पहले, प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने अब जेलर कलाकारों के लिए शानदार पोस्टरों की एक सीरीज को लॉन्च किया है, जो हिट अमेरिकी नेटवर्क सीरीज ब्रेकिंग बैड से प्रेरित है. पोस्टर दिखने में वाकई कमाल के लग रहे हैं पोस्टर पर टैगलाइन लिखी है मैक्लारे में नहीं हूं मैं खतरा हूं अन्य पोस्टर में उनके को-एक्टर्स और मेहनलाल, शिवराजकुमार, जैकी श्रॉफ और विनायकन के किलर पोज जबरदस्त लग रहे हैं रिसेप्स के मुनाबिक नेरसन दिलीपकुमार 5 दिसंबर को सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म का प्रमो शूट करने की योजना बना रहे हैं रिसेप्स के मुनाबिक नया प्रमो रजनीकांत के 74 वें जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा. प्रमो शूट चेंहई मेहेन की उम्मीद है हालांकि फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रमो मेवास्तव मे क्या होगा. नेरसन दिलीपकुमार की 2023 की बॉक्सऑफर जेलर ने कई रिकॉर्ड तोड़े साथ ही फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई थी. रिसेप्स के मुनाबिक रजनीकांत के पूरे वामद वृत्त से सीक्वल में एक अहम रोल के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है हालांकि ऑफिशियल पुष्टि अभी बाकी है जेलर 2 रजनीकांत की सुपर-हिट 2023 क्रहम-श्चिर जेलर का सीक्वल है एक्टर ने फिल्म में एक स्टिपेंड प्लेसकर की भूमिका निभाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. जो तमिलनाडु समेत सुपरस्टार के लंबे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई. फिल्म में थलाइवा के साथ मेहनलाल, शिवा राजकुमार, राम्या कृष्णन, जैकी श्रॉफ, तमना भाटिया, योगी बाबू और वसंत रवि जैसे कलाकार शामिल हैं.

चर्वतन निदेशालय (ईडी) ने 29 नवम्बर को एक्ट्रेस शिल्पा शेष्टी और उनके पति राज कुंद्रा के मुंबई स्थित बंगले और ऑफिस में छापेमारी की। इसके अलावा, ईडी ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 15 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी अधिकारियों डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज किया, जोकि पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े हैं। इसके अलावा उनके कुछ बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। यह छापेमारी उनके खिलाफ पोर्नोग्राफी नेटवर्क मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई। राज कुंद्रा को जून 2021 में कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में दो महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें सितंबर 2021 में जमानत मिल गई। इसके बाद से इस मामले की जांच चल रही है। ईडी ने कुछ आरोपियों के बैंक खाते को फ्रीज किया है। वह अब इन खातों से पैसों को लेनदेन नहीं कर सकते हैं। ईडी की टीम ने मुंबई लखनऊ और प्रयागराज से संयुक्त रूप से छापेमारी की। ईडी के सूत्र के मुताबिक, कठकुड़ियां के रोहित चौरसिया को नोटिस जारी कर 4 दिसंबर को मुंबई ईडी कार्यालय में तलब किया गया है। रोहित चौरसिया होगी विस्तार से पूछताछ होगी। शिल्पा शेष्टी और राज कुंद्रा से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्यवाही हुई पूरी लेकिन तपतीश जारी है। उत्तरप्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जांच एजेंसी के रडार पर हैं। विस्तार से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ आज बड़ी कार्यवाही हो सकती है। जांच एजेंसी के रडार पर अरविंद श्रीवास्तव और उससे जुड़े कई लोग भी हैं। अरविंद श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके का रहने वाला है। कानपुर में ईडी ने श्यामनगर में अरविंद श्रीवास्तव के घर में छापेमारी की थी। पिछले काफी समय से सिंगापुर में रह रहा अरविंद ही कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस संभालता था। सूत्र के मुताबिक आरोप है कि अश्लील फिल्मों की करोड़ों रुपये की काली कमाई खपाने को अरविंद श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी व पिता के बैंक खातों का प्रयोग किया। ईडी ने राज कुंद्रा के सहयोगियों के घरों पर भी छापेमारी की और कुशीनगर से एक सॉफ्टवेयर के यहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुशीनगर स्थित पडरोना की राजपूत कालोनी व कुबेरस्थान के कठकुड़ियां में दो संदिग्धों से 12 घंटे पूछताछ चली। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी के सूत्र का कहना है कि तपतीश जारी है। **MgQhZ**



ब्लैक आउटफिट पहन नेहा मलिक ने दिखाया बोल्ड अवतार, भोजपुरी क्वीन की हाटनेस देख फैंस के उड़े होश



भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक आए दिन अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस से सोशल मीडिया का पारा बढ़ाती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस नेहा मलिक ने अपने लेटेस्ट किलर फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में उनका किलर लुक देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। एक्ट्रेस नेहा मलिक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करती हैं तो वो तेजी से वायरल होने लगती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट हॉट फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं।

दरअसल, मधु चोपड़ा 'समथिंग बिग रॉक शो' पॉडकास्ट के होस्ट रोज़िगो कैनेलस के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्होंने बताया कि बेटी प्रियंका को सात साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जिसको लेकर उन्हें आज भी अफसोस होता है। प्रियंका चोपड़ा अपनी मां मधु चोपड़ा के बेहद करीब हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे के लिए पोस्ट शेयर करती रहीं हैं। मां से भले प्रियंका दूर हैं, लेकिन दोनों का बॉन्ड इसी से पता चलती है कि हर बात में दोनों एक दूसरे का जिक्र करती हैं। मधु चोपड़ा ने कहा कि उनका यह फैसला गर्व और अफसोस दोनों से भरा है। हालांकि, यह एक अफसोसजनक फैसला था, लेकिन प्रियंका ठीक निकलीं और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गईं।